



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 29 अक्तूबर, 1984/7 कार्तिक, 1986

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अक्टूबर, 1984

संख्या स्था० स्व० (ख) 3-15/82.—निगम शिमला जिला शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 321 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियाँ जिसका नाम "शिमला नगर निगम (कुत्तों का नियन्त्रण) उप-विधि, 1984" है, जिनका हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उक्त अधिनियम की धारा 397 की अपेक्षानुसार अनुमोदन कर दिया है, जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है और नगर निगम शिमला के क्षेत्र में तुरन्त प्रवृत्त होगी।

शिमला नगरनिगम (कुत्तों का नियन्त्रण) उप-विधि, 1984

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम शिमला नगरनिगम (कुत्तों का नियन्त्रण) उप-विधि, 1984 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ.—इन उप-विधियों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) अधिनियम से हिमाचल प्रदेश नगरनिगम अधिनियम, 1979 (1980 में अधिनियम संख्यांक 9) अभिप्रेत है।

(2) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. शिमला नगर निगम की परिसीमा के भीतर रखे गये या लाये गये प्रत्येक कुत्ते का स्वामी प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल को या उससे पूर्व या इसके लाये जाने से सात दिनों के भीतर 15 रुपये रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने पर कुत्ते को नगरनिगम के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत करेगा।

4. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप नगर निगम के कार्यालय में आवेदन-पत्र देने पर उल्लेख करवाया जाएगा।

5. नगर निगम के कार्यालय में सम्पक रूप से भरे गये रजिस्ट्रीकरण के प्ररूप की प्राप्ति पर स्वामी को नगर निगम द्वारा धातु का एक टिकट दिया जायेगा।

6. रजिस्ट्रीकरण 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक की बारह मास की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

7. स्वामी कुत्ते को सभी समय एक पट्टा पहनाये रखेगा जिसमें प्रदान कि गये धातु का टिकट दृढ़ता के साथ बंध रखेगा।

8. यदि कोई कुत्ता जो इन उप-विधियों के खण्ड 7 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण धातु का टिकट नहीं पहने है किसी सार्वजनिक स्थान में पाया जायेगा तो उसे हटा दिया जायेगा और यदि स्वामी द्वारा सात दिन के भीतर दावा नहीं किया जाता है तो उसे शिमला नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशों के अधीन नष्ट या अन्यथा निपटाया जा सकेगा।

9. शिमला नगर निगम की परिसीमा से स्वामी की अनुपस्थिति के दौरान कुत्ता जिस व्यक्ति के कब्जा या प्रभारी में है वह इन उप-विधियों के प्रयोजनों के लिए उसका स्वामी समझा जायेगा।

10. इन उप-विधियों का कोई भी उल्लंघन जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा और किन्तु पच्चास रुपये से कम का नहीं होगा और चालू भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे उल्लंघन या भंग के चालू रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

11. यह उप-विधियाँ उन कुत्तों को लागू नहीं होगी जो शिमला नगर निगम की परिसीमा के भीतर कुत्तों की प्रदर्शनी के लिए लाये गए हों और शिमला कुत्ता प्रदर्शनी के सचिव द्वारा उन रूप में प्रमाणित किए गए हों:

परन्तु यह तब जबकि ऐसे कुत्ते शिमला नगर निगम की परिसीमा के भीतर एक सप्ताह से अधिक नहीं रखे जाते हैं।

12. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 255 तारीख 1 अप्रैल, 1913 द्वारा पुष्ट की गई उप-विधि, जो शिमला नगर निगम की परिसीमा के भीतर प्रवृत्त है, इसके द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होने हुए भी इस प्रकार निरसित उप-विधि के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई भी बात या कार्यवाही इन उप-विधियों के द्वारा या अधीन प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी मानो उस दिन, जिस दिन ऐसी बात या कार्यवाही की गई थी, यह उप-विधियाँ प्रवृत्त थी।

आदेश द्वारा,
अंतर सिंह
सचिव।

Y [Authoritative English text of notification No. LSG-B (3)-15/82, dated 19-9-84 is here by published for general information as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 19th September, 1984

No. LSG-B (3)-15/82.—The following bye-laws entitled “Shimla Municipal Corporation (Control of Dogs) Bye-Laws, 1984” made by the Municipal Corporation Shimla, District Shimla in exercise of the powers conferred by section 321 (1) of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979 (Act No. 9 of 1980) having been approved by the Governor, Himachal Pradesh as required under section 397 of the aforesaid Act are hereby published for general information and shall come into force at once within the area of Municipal Corporation Shimla:

SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION (CONTROL OF DOGS) BYE-LAWS, 1984

1. Short title and commencement.—(1) These Bye-laws may be called the Shimla Municipal Corporation (Control of Dogs) Bye-laws, 1984.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.—In these Bye-laws, unless the context otherwise requires,—

(1) “Act” means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979 (Act No. 9 of 1980).

(2) “Section” means a section of the Act.

3. The owner of every dog kept or brought within the limits of Shimla Municipal Corporation shall on or before the first day of April in each year or within 7 days of its arrival, register the dog at the office of the Municipal Corporation on payment of Rs. 15/- as registration fee.

4. The form for registration shall be provided on an application at the office of the Municipal Corporation.

5. On receipt of the form of registration duly filled in at the office of the Municipal Corporation, the owner shall be supplied by the Corporation with a metal ticket.

6. The period for which the registration shall hold good, shall be for the 12 months from the 1st April to next 31st March in each year.

7. The owner shall cause the dog to wear at all time a collar with the metal ticket supplied, firmly secured thereto.

8. Any dog not wearing metal ticket of registration in accordance with clause 7 of these bye-laws may, if found in any public place be removed and will be liable to be destroyed or otherwise disposed of under the orders of the Health Officer, Municipal Corporation, Shimla, if not claimed within 7 days by the owner.

9. For the purpose of these bye-laws any person in possession or charge of a dog during the absence of the owner from the limits of M. C. Shimla shall be held to be the owner of the same.

19. Any contravention of these bye-laws shall be punishable with a fine which may extend to Rs. 200/- but shall not be less than Rs. 50/- and in case of continuing breach additional fine which may extend to rupees 25/- for every day during which such contravention or breach continues.

11. The above bye-laws shall not apply to such dogs which are brought within the limits of Municipal Corporation Shimla for show purpose and are certified as such by the Secretary of the Shimla Dog Show; provided that such dogs are not kept within the limits of Municipal Corporation Shimla for more than one week.

12. *Repeal and Savings.*—(1) The bye-laws confirmed by the Punjab Government vide their notification No. 255, dated the 7th April, 1913 which are in force within the limits of Municipal Corporation, Shimla are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done, or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the bye-laws so repealed shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these bye-laws as if these bye-laws were in force on the day on which such thing was done or was taken.

By order.
ATTAR SINGH,
Secretary.

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, UNA, DISTRICT UNA, H.P.

NOTIFICATION

Una, the 19th September, 1984

No. FDS-UNA-6-1136/82-5507-5553.—In continuation to this office notification issued vide No. FDS-UNA-6-1136/4871-4907 dated 17-8-84 and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (1) (e) of the H. P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, S. Padmanabhan, District Magistrate, Una, District Una do hereby order that the rates fixed in the said notification will remain in force for the next 30 days from the date of issue of this notification throughout Una district.

S. PADMANABHAN,
District Magistrate,
Una, District Una, H.P.

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 20th September, 1984

No. 10(1)34/83-16234-68.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 3 of H. P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Y. R. Mahajan, I.A.S., Director, Food and Supplies, Himachal Pradesh, hereby fix with immediate effect the maximum ex-mill

prices of wheat products manufactured out of the wheat being supplied to mills/chakkies @ Rs. 172/- per quintal ex. Food Corporation of India godown to Roller Flour Mills/Chakkies:

Sr. No. 1	Commodity 2	Percentage of extraction 3	Rates per quintal 4
1.	Maida/Suji	60 %	Rs. 236/-
2.	Resultant atta (Manufactured by M/s Himachal Flour Mills, Kangra and M/s Amar Roller Flour Mills, Parwanoo).	20 %	Rs. 130/-
3.	Bran	20 %	Rs. 106/-
Wholemeal atta manufactured by:—			
1.	M/s Shimla Roller Flour Mills, Shimla.	100 %	Rs. 192.55
2.	M/s Himachal Flour Mills, Kangra, M/s Amar Roller Flour Mills, Parwanoo, District Solan.	100 %	Rs. 188.80 (Out of Public Distribution System Wheat only).
3.	M/s Laxmi Flour Mills/M/s Om Oil and Flour Mills/M/s Amar Flour Mills, Parwanoo, District Solan.	100 %	Rs. 184.55
4.	Other Chakkies	100 %	Rs. 183.75 (Plus actual handling as approved by the respective Deputy Commissioners).

The entire atta will be sold under the directions of the Director, Food and Supplies, Himachal Pradesh.

There is no distribution control on maida, suji and bran subject to within the ceiling of maximum prices fixed above.

This notification supersedes the earlier notification issued vide No. 10 (1) 34/83/7388-7428, dated 27-4-1984.

Y. R. MAHAJAN,
Director.

राजस्व विभाग

(स्टैम्प-रजिस्ट्रेशन)

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 सितम्बर, 1984

संख्या 2-18/61-रैव-ए.—भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 74 और हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (1) तथा धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार द्वारा स्टैम्प की आपूर्ति एवम् वितरण हेतु बनाये गये नियमों से व्युत्पन्न प्राधिकार के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश स्टैम्प अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने हेतु सहर्ष निम्नलिखित नियम बतते हैं :—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Stamp (Amendment) Rules, 1984.

(ii) They shall come into force at once.

2. *Amendment to rule 26.*—For the word and figure “Rupees 500/-” occurring in clause (i) (a) of rule 26 of the Himachal Pradesh Stamp Rules, 1973 (hereinafter referred to as the “said rules”), the word and figure “Rupees 1,000/-” shall be substituted.

3. *Amendment of rule 28*—For the word and figure “Rupees 500/-” occurring in clauses (ix) and (x) of rule 28 of the said rules, the word and figure “Rupees 1,000/-” shall be substituted.

4. *Condition for sale of stamps in any single transaction exceeding Rs. 500/- in value.*—After rule 28 of the said rules, the following rule 28-A shall be added, namely:—

Rule 28-A. if in any single transaction stamp exceeding Rupees 500/- in value is required by any litigant the licensee shall sell the same subject to the condition that the litigant or his advocate produces before the Stamp Vendor, in the High Court a certificate issued by the Registrar, and, before the Stamp Vendor in the District Courts, a certificate issued by the Superintendent of the District Courts to the effect that stamps are *bona fide* required for the purpose of instituting litigation in the High Court or in the District Court, as the case may be.

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANGRA AT DHARAMSHALA

NOTIFICATION

Dharamshala, the 27th August, 1984

No. FDS-D/shala-83-10915-90.—In supersession of all previous orders regarding fixation of maximum retail sale rates and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (i) (e) of Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977 as amended *vide* Himachal Pradesh Govt. Notification No. FDS-A-3(2)/77, dated 30-10-1980, I, Dev Swarup,

District Magistrate, Kangra at Dharamshala hereby fix the maximum retail sale rates inclusive of all taxes of the following commodities as under:—

Sl. No.	Name of the articles as per schedule	Name of the commodity	Maximum retail sale rate inclusive of all taxes	
1	2	3	4	
1.	2	Bread	1. Rs. 1.60 per bread of 350 gm. manufactured locally in any town/city of Kangra district. 2. Rs. 1.65 per bread of 350 gm. received from outside the locality of any town/city duly manufactured within Kangra district or from outside Kangra district.	
2.	12	Meat Chicken Broiler Fish	Rs. 17/- per kg. Rs. 21/- Rs. 24/- Categories;	These rates are applicable for the whole of District.
			” ” ”	
The maximum retail price/ sale price including all taxes per kg.			Kalbans and Gildbata	Mali, Singharas, Soul and all other
			Un-fried Rs. per kg.	Fried Rs. per kg.
Nurpur and Dehra sub-division			10.50	18.00
Dharamshala town & Kangra sub-division			12.50	21.00
Palampur sub-division			12.50	21.00
3.	13	EGGS		
Nurpur Sub-Division		0.58 per egg	Rs. 7.00 per Doz.	Large above 50 gm.
		0.54 ”	Rs. 6.30 ”	Small below 50 gm.
Dehra Sub-Division & Kangra Sub-Division including Dharamshala & Palampur sub-division		0.60 ”	Rs. 7.20 ”	Large above 50 gm.
		0.55 ”	Rs. 6.50 ”	Small below 50 gm.
4.	18	MILK/CURD		
1. Kutch Milk			Rs. 3.00 per litre	These rates will be applicable for the whole of Kangra district.
2. Boiled Milk			Rs. 3.40 ” ”	
3. Sweetened Milk			Rs. 3.90 ” ”	
4. Curd			Rs. 4.50 ” kg.	

1	2	3	4
17.	Cooked food served in Dhabas (Cheap eating houses located in the jurisdiction/Municipal Committee, Notified Area Committee in the district)		
1.	Diet (including one vegetable, one Dal and Chapati and Rice)	Rs. 3.25	
2.	Chapati of 50 gm.	Rs. 0.30	
3.	Rice	Rs. 1.25 per plate	
4.	Vegitable (Special)	Rs. 1.65	„
5.	Meat (Minimum total weight of pieces 150 gm.)	Rs. 5.75	„
6.	Chicken (Minimum total weight of pieces 200 gm.)	Rs. 7.50	„

This notification will remain in force for a period of one month from the date of issue or till new rates are notified whichever is later.

DEV SWARUP,
District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 30 अक्टूबर, 1984/8 कार्तिक, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 30 अक्टूबर, 1984

क्रमांक एल० एल० आर०-डी०(6) 54/84.—हिमाचल प्रदेश पैसन्जर्ज एण्ड
गुड्स टैक्सेशन (अप्रैण्डमेण्ट) विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 21) जैसा कि
राज्यपाल महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत दिनांक 25 अक्टूबर,